IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 4, June 2026
Impact Factor: 8.2

मध्य प्रदेश के कृषकों के आर्थिक विकास में जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों का योगदान: बालाघाट जिले के विशेष संदर्भ में

शैलेन्द्र कुमार मेश्राम[1], डॉ. बसंती मैथ्यु[2]
[1] शोधार्थी, [2] प्रोफेसर,
रबींद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय, भोपाल, मध्य प्रदेश, भारत

सारांश : ***भारतीय अर्थव्यवस्था और ग्रामीण आजीविका का मुख्य आधार कृषि है। प्रस्तुत शोध पत्र मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में कृषकों के आर्थिक विकास में 'जिला सहकारी केंद्रीय बैंक' (DCCB) की भूमिका और योगदान का विश्लेषणात्मक मूल्यांकन करता है। अध्ययन में प्राथमिक (300 कृषकों से प्रश्नावली) एवं द्वितीयक (बैंक के 2017-18 से 2021-22 तक के प्रतिवेदन) समंकों का उपयोग किया गया है। परिणामों से ज्ञात होता है कि बालाघाट जिले के लगभग 98.93% कृषक परिवार सहकारी समितियों से जुड़े हुए हैं। बैंक द्वारा अल्पावधि (KCC), मध्यमकालीन और दीर्घकालीन ऋण योजनाओं के माध्यम से संस्थागत साख उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे कृषकों को साहूकारों के शोषण से मुक्ति मिली है और कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई है। हालाँकि, जटिल दस्तावेजीकरण और ऋण वसूली जैसी कुछ प्रशासनिक चुनौतियाँ अभी भी विद्यमान हैं। कुल मिलाकर, यह बैंक जिले में वित्तीय समावेशन और कृषक समृद्धि का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है।***

कुंजी शब्द : **कृषि विकास, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक (DCCB), ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बालाघाट जिला, वित्तीय समावेशन, संस्थागत ऋण, प्राथमिक कृषि साख समितियां (PACS)।**

I. प्रस्तावना

भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है तथा कृषि क्षेत्र न केवल देश की खाद्य सुरक्षा का आधार स्तम्भ है, बल्कि ग्रामीण आजीविका, रोजगार तथा क्षेत्रीय संतुलित विकास का प्रमुख माध्यम है। मध्यप्रदेश जैसे कृषि प्रधान राज्य में कृषि केवल उत्पादन का साधन नहीं, बल्कि जीवन पद्धति है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पूंजी की उपलब्धता सदैव से एक गंभीर समस्या रही है। परंपरागत रूप से किसान साहूकारों एवं महाजनों से ऊँची ब्याज दरों पर ऋण लेते रहे हैं। इस परिस्थिति में सहकारिता आंदोलन एक सामाजिक-आर्थिक सुधार के रूप में उभरा,

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 4, June 2026 Impact Factor: 8.2

जिसका मूल उद्देश्य कृषकों को सुलभ और सस्ता संस्थागत ऋण उपलब्ध कराना था। इसी ढांचे के अंतर्गत जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक (DCCBs) स्थापित किए गए, जो प्राथमिक कृषि साख समितियों (PACS) तथा राज्य सहकारी बैंक के मध्य सेतु का कार्य करते हैं। बालाघाट जिला, जो अपनी भौगोलिक, सामाजिक एवं आर्थिक विशेषताओं (मुख्यतः धान उत्पादक क्षेत्र) के कारण विशिष्ट है, वहाँ अधिकांश कृषक लघु एवं सीमांत श्रेणी में आते हैं। ऐसी स्थिति में बालाघाट का जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक कृषकों को ऋण, बीज, उर्वरक वितरण और अन्य वित्तीय सेवाएँ प्रदान कर उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

II. साहित्य की समीक्षा (Review of Literature)

शोध कार्य की वैज्ञानिकता पूर्व शोध साहित्य की समीक्षा पर आधारित होती है। इस विषय से संबंधित प्रमुख पूर्व अध्ययन निम्नवत् हैं:
गिरी मनीषा सुभाष (2024): इन्होंने महाराष्ट्र के आर्थिक विकास पर DCCBs के प्रभाव की जांच की और निष्कर्ष निकाला कि ये बैंक वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण हैं, यद्यपि उन्हें परिचालन संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

अनिल कुमार सोनी और हरजिंदर पाल सिंह सलूजा: इनके अध्ययन के अनुसार, सहकारी बैंकों की प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) के माध्यम से ग्रामीण भारत तक व्यापक पहुँच है। इन्होंने 'किसान क्रेडिट कार्ड योजना' को किसानों के लिए एक मील का पत्थर बताया है।

सहानी मोहन (2019) एवं कुमार मुकेश (2019): इन शोधों में पाया गया कि सहकारी बैंक ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य पहलू हैं, परंतु वर्तमान में वे तकनीकी पिछड़ेपन, फंड की कमी और अकुशल सदस्यों जैसी चुनौतियों से जूझ रहे हैं।

कपूर सत्संगी और उषा (2016): इनके अध्ययन के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी बैंक साहूकारों के शोषण से बचाते हैं और कम ब्याज दर पर ऋण देते हैं, लेकिन गैर-निष्पादित संपत्तियों (NPA) की बढ़ती समस्या इनके क्रेडिट साइकिल में रुकावट डाल रही है।

III. अध्ययन का उद्देश्य (Objective)

इस शोध का मुख्य उद्देश्य बालाघाट जिले के कृषकों के आर्थिक विकास में 'जिला सहकारी केंद्रीय बैंक (DCCB)' द्वारा प्रदत्त वित्तीय संसाधनों, ऋण योजनाओं (अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन) की भूमिका का मूल्यांकन करना तथा कृषि वित्त संबंधी कृषकों की समस्याओं का अध्ययन कर समाधान प्रस्तुत करना है।

IV. परिकल्पना (Hypothesis)

H_1: जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, बालाघाट द्वारा संचालित विभिन्न ऋण योजनाओं और संस्थागत वित्त वितरण से जिले के कृषकों को समय पर पूंजी की प्राप्ति होती है, जिसका उनके समग्र आर्थिक विकास और कृषि उत्पादकता पर प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 4, June 2026
Impact Factor: 8.2

V. शोध प्रविधि (Research Methodology)

समंक संकलन:

प्राथमिक समंक: प्रत्यक्ष सर्वेक्षण पद्धति के माध्यम से बालाघाट जिले के 300 चयनित कृषकों से प्रश्नावली भरवाकर डेटा संकलित किया गया।

द्वितीयक समंक: जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित बालाघाट के वार्षिक प्रतिवेदनों (वर्ष 2017-18 से 2021-22), नाबार्ड (NABARD), और सांख्यिकी कार्यालयों से आंकड़े प्राप्त किए गए।

सांख्यिकीय तकनीक:

प्राप्त समंकों के वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए माध्य, प्रमाप विचलन,विचरण गुणांक (CV), टी-टेस्ट (t-test) तथा चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) जैसे सांख्यिकीय सूत्रों का उपयोग किया गया है।

VI. परिणाम एवं निष्कर्ष (Results and Findings)

तालिका 1: कुल कृषक परिवारों का विवरण (2017-18 से 2021-22)

वर्ष	कुल कृषक परिवार	समिति के सदस्य कृषकों की संख्या	सहकारिता से जुड़ाव (प्रतिशत में)
2017-2018	3,15,900	3,13,958	99.38%
2018-2019	3,17,000	3,13,958	99.04%
2019-2020	3,17,000	3,13,414	98.89%
2020-2021	3,17,000	3,13,506	98.90%
2021-2022	3,17,000	3,13,607	98.93%

जिले में कुल 3,17,000 कृषक परिवार हैं, जिनमें से अधिकांश सहकारी समिति के सदस्य हैं। तालिका 1 से स्पष्ट है कि बालाघाट जिले में लगभग 98.93% कृषक परिवार सहकारिता नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। यह अत्यंत संतोषजनक स्तर है जो दर्शाता है कि कृषि यहाँ आजीविका का मुख्य आधार है और संस्थागत साख प्रणाली की पहुँच लगभग प्रत्येक घर तक है।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 4, June 2026
Impact Factor: 8.2

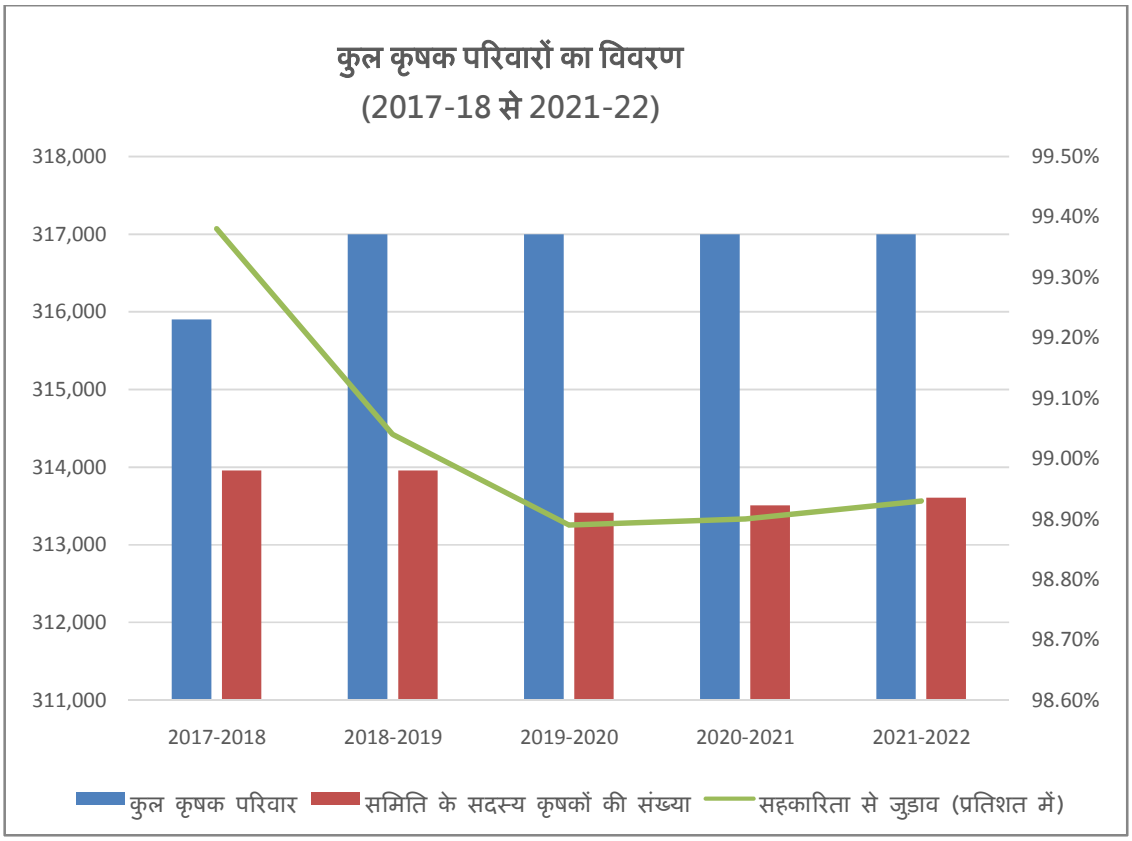

तालिका 2: जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक बालाघाट द्वारा प्रदत्त अंशपूंजी (लाख रुपये में)

वर्ष	सहकारी समितियाँ	राज्य शासन	नाम मात्र सदस्य	आईसीडीपी (ICDP)	कुल योग
2017-18	2129.10	0.00	4.33	53.31	2186.74
2018-19	2129.10	721.62	4.34	32.38	2887.44
2019-20	2358.87	721.62	4.35	11.44	3096.28
2020-21	2358.87	721.62	4.36	24.43	3109.28
2021-22	2382.93	721.62	4.37	9.11	3118.03
माध्य (Mean)	2271.77	577.30	4.35		

अंशपूंजी बैंक की स्वामित्व संरचना को प्रदर्शित करती है और ऋण देने की क्षमता का आधार होती है। बैंक की कुल अंशपूंजी वर्ष 2017-18 के 2186.74 लाख रुपये से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 3118.03 लाख रुपये हो गई है। इसमें सहकारी समितियों (औसत 2271.77 लाख) और राज्य शासन (721.62 लाख) का प्रमुख योगदान है, जो बैंक की निरंतर मजबूत होती वित्तीय स्थिति को दर्शाता है।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 4, June 2026
Impact Factor: 8.2

VII. निष्कर्ष (Conclusion)

उपरोक्त सांख्यिकीय विश्लेषण और प्राथमिक समंकों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, बालाघाट जिले के कृषकों के आर्थिक विकास का एक सशक्त और अपरिहार्य माध्यम है।

जिले के लगभग 99% कृषकों का इससे जुड़ाव इस बात का प्रमाण है कि बैंक ने किसानों को साहूकारों के चंगुल से सफलतापूर्वक बाहर निकाला है। अंशपूंजी में निरंतर वृद्धि बैंक की वित्तीय सुदृढ़ता को दर्शाती है। बैंक द्वारा केवल फसल ऋण ही नहीं, बल्कि ट्रैक्टर ऋण, लघु सिंचाई, पशुपालन और संयुक्त देयता समूह (JLG) जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो कृषकों की आय में विविधीकरण ला रही हैं।

हालाँकि, शोध के दौरान यह भी सामने आया कि ऋण प्राप्ति की प्रक्रिया में जटिल दस्तावेजीकरण (बंधक, सर्च रिपोर्ट आदि) और निरक्षरता के कारण किसानों को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यदि बैंक ऋण प्रक्रियाओं को तकनीकी रूप से अधिक सरल बनाए, वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा दे और NPA को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए, तो यह कृषकों की आय दोगुनी करने के राष्ट्रीय लक्ष्य में और भी अधिक मील का पत्थर साबित होगा।

संदर्भ :

1. गिरी, एम. एस. (2024). महाराष्ट्र के आर्थिक विकास पर जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों का प्रभाव। स्टेट डेवलपमेंट रिपोर्ट्स।
2. कुमार, एम. (2019). ग्रामीण भारत में सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में चुनौतियाँ और तकनीकी अपनाव।
3. सहानी, एम. (2019). भारत में सहकारी बैंकिंग क्षेत्र और संस्थागत साख संरचना पर एक अध्ययन।
4. सोनी, ए. के., एवं सलूजा, एच. पी. एस. (बिना तिथि). सहकारी संस्थागत ऋण संरचना में पीएसीएस (PACS) और किसान क्रेडिट कार्ड की भूमिका।
5. कपूर, एस., एवं उषा. (2016). साहूकारों के शोषण को समाप्त करने और एनपीए (NPA) के प्रबंधन में सहकारी बैंकों की भूमिका।
6. मिश्रा, एस. के. के., एवं उडुपा, पी. आर. (2018). प्राथमिक कृषि ऋण समितियों और सहकारी बैंकों में वित्तीय दबाव और दक्षता।
7. रेउल, डी. (2018). थाने जिला केंद्रीय सहकारी बैंक का वित्तीय विश्लेषण।
8. जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, बालाघाट. (2022). 111वाँ वार्षिक प्रतिवेदन (2017-18 से 2021-22). मध्यप्रदेश।